RAJYA SABHA

Thursday, the 3rd August, 1995/ 12 Sravana, 1917 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Investments on Drinking Water Schemes

*61. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the investment made by Government on various schemes pertaining to the supply of safe drinking water during the Eighth Plan period;

(b) whether Government have reviewed those schemes; and

(c) if so, the State-wise achievements made under those schemes so far?

THE MINISTER IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (DR. JAGANNATH MISHRA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The outlay for drinking water supply in rural areas for the VIIIth Five Year Plan is Rs. 5100 crore in the Central Sector and Rs. 4954.23 crore in the State Sector Minimum Needs Programme. The investment made during the first three years of the VIIIth Plan (1992-93 to 1994-95) is Rs. 2005.988 crore under Rajiv Gandhi National Drinking Water Mission, comprising of Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme, Mini-Mission Projects, Sub-Missions and other supporting programmes. The investment made by the States/UTs under MNP was Rs. 2572.103 crore during the same period from 1992-93 to 1994-95. The approved outlay for 1995-96 is Rs. 1110 crore (Rs. 456.507 crore already released) under Central Section and Rs. 1185.57 crore (Rs. 102.035 crore spent upto June, 1995) under the State Sector Minimum Needs Programme.

(b) The implementation of the programmes/schemes is reviewed from time to time.

(c) The details regarding the State-wise achievements made under those programmes so far in terms of villages/ habitations covered and population benefited are at enclosed as statement "A" and statement "B".

Statement "A"

Sl. No.	State/UT	No. of Villages/Habitations covered during				
		1992-93	1993-94	1994-95*	1995-96*	
					Target	Achievement (Up to June 1995)
1.	Andhra Pradesh	691	1408	2774	3100	129
2.	Arunachal Pradesh	169	149	148	150	0
3.	Assam	156	751	1536	1500	84
4.	Bihar	5188	3530	7219	17621	389
5.	Goa	54	56	62	54	0
6.	Gujarat	456	458	464	1100	81
7.	Haryana	334	700	845	1000	128
8.	Himachal Pradesh	573	570	800	925	259

9.	J. & K.	94	76	107	350	0
10.	Karnataka	5056	5150	4935	10414	542
11.	Kerala	252	164	214	1065	1
12.	Madhya Pradesh	5666	5963	12138	9000	2655
13.	Maharashtra	814	1373	6828	6000	2115
14.	Manipur	86	155	170	310	0
15.	Meghalaya	688	743	363	606	6
16.	Mizoram	154	167	222	240	17
17.	Nagaland	49	65	0	124	0
18.	Orissa	1600	5460	7351	6000	1842
19.	Punjab	650	343	426	684	63
20.	Rajasthan	2010	2328	3054	4500	340
21.	Sikkim	18	70	66	88	4
22.	Tamil Nadu	2663	3751	3808	2500	189
23.	Tripura	214	215	610	795	184
24.	Uttar Pradesh	4964	6047	11283	12953	1784
25.	West Bengal	1715	1750	5372	5578	542
26.	A&N Islands	18	19	20	15	0
27.	Chandigarh	0	0	0	0	0
28.	D&N Haveli	0	0	112	12	0
29.	Daman & Diu	4	2	11	29	0
30.	Delhi	0	0	0	0	0
31.	Lakshadweep	4	4	2	5	0
32.	Pondicherry	20	21	28	28	3
	TOTAL:	34360	41488	70968	86746	11357

* Villages/Habitations

Statement "B"

Sl. No.	State/UT	Population covered (in lakhs) during				
		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	
					Target	Achievement (Up to 6/95)
1.	Andhra Pradesh	9.959	1.978	2.774	34.670	2.661
2.	Arunachal Pradesh	0.240	0.220	0.202	0.150	0.000
3.	Assam	2.624	2.945	3.700	4.850	0.335
4.	Bihar	19.720	2.780	14.330	32.500	0.800
5.	Goa	0.416	0.289	0.462	0.402	0.000
6.	Gujarat	2.731	3.051	6.355	8.170	0.490
7.	Haryana	6.735	15.155	13.980	11.125	2.160
8.	Himachal Pradesh	0.610	5.287	0.402	0.450	0.105
9.	J. & K.	0.718	0.601	0.858	0.750	0.000
10.	Karnataka	10.316	10.255	24.230	49.030	1.417
11.	Kerala	4.998	0.769	5.436	5.000	0.002
12.	Madhya Pradesh	21.760	25.550	33.180	25.000	7.240
13.	Maharashtra	17.760	15.640	33.377	21.250	9.684
14.	Manipur	0.662	0.180	0.943	1.620	0.000

15.	Meghalaya	0.826	0.001	0.541	1.200	0.016
16.	Mizoram	0.353	0.336	0.561	0.530	0.026
17.	Nagaland	0.273	0.215	0.000	0.625	
18.	Orissa	5.114	1.167	10.290	7.800	2.500
19.	Punjab	6.912	2.391	3.310	6.160	0.478
20.	Rajasthan	2.803	1.981	1.362	4.220	0.188
21.	Sikkim	0.071	0.395	0.054	0.094	0.003
22.	Tamil Nadu	24.510	24.566	24.235	15.000	1.460
23.	Tripura	0.700	0.253	0.959	0.990	0.116
24.	Uttar Pradesh	25.157	36.996	29.893	20.000	5.408
25.	West Bengal	6.388	9.941	15.330	11.150	0.860
26.	A&N Islands	0.000	0.000	0.001	0.071	
27.	Daman & Diu	0.000	0.237	0.381	0.203	
28.	Lakshadweep	0.000	0.000	0.000	0.202	0.000
29.	Pondicherry	0.032	0.000	0.509	0.685	0.014
30.	Delhi	0.000	0.000	0.000	0.472	0.000
31.	Chandigarh	0.000	0.000			
32.	D & N Haveli	0.000	0.000	0.000	0.621	0.000
	TOTAL:	172.388	163.179	227.655	264.990	35.955

SHRI BHAGABAN MAJHI: Mr. Chairman, Sir, despite massive investments made in the drinking water programmes, the benefit of these programmes has not reached the tribal, hilly and inaccessible areas. I would like to know from the hon. Minister if he proposes to introduce any Central Scheme to provide drinking water exclusively in the hilly, tribal and inaccessible areas.

डा० जगन्नाथ मिश्र: यह जलापूर्ति की योजना केन्द्र और राज्य सरकारों की सम्मिलित योजना है। केन्द्र सरकार की इसमें सहायता है। परन्तु जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके लिए खास सहायता पूरी की पूरी भारत सरकार की ओर से दी जाती है और उनको प्राथमिकता भी दी जा रही है।

SHRI BHAGABAN MAJHI: Sir, a number of schemes have been introduced by the Government to ensure safe drinking water to the people of this country, but it is regrettable that still there are problem villages in every State. I want to know from the hon. Minister what steps are being taken by him to provide safe drinking water to every village, the target fixed therefor and the efforts made to achieve that target.

डा० जगन्नाथ मिश्र: प्रत्येक गांव और प्रत्येक बस्ती में शुद्ध जल की आपूर्ति की जाए यह सरकार का लक्ष्य है।

श्री चतुरानन मिश्र: जो लोग अंग्रेजी में पूछते हैं उनका अंग्रेजी में जवाब दीजिए।

डा० जगन्नाथ मिश्र: इस समय देश में 1,40,975 बस्तियां हैं जहां जलापूर्ति के कोई स्रोत नहीं है। 4,30,377 बस्तियां हैं जहां आंशिक रूप से जल की आपूर्ति की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इन दोनों श्रेणियों के गांवों में जहां पानी के स्रोत नहीं है और जहां आंशिक रूप से जलापूर्ति है—10 लीटर तक की आपूर्ति होती है जबकि एक मनुष्य की आवश्यकता कम से कम 40 लीटर पानी की है—पूरा पानी मिले। इसलिए सरकार ने हाल में निर्णय लिया है कि स्वतंत्रता के पचासवें साल यानी 1997 के अप्रैल महीने तक इन सभी गांवों को शुद्ध पानी की व्यवस्था दे दी जाए।

MR. CHAIRMAN: We have a Short Duration Discussion today on this subject. Therefore, I will ask only few Members to put supplementaries this time.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, many of our cities are facing shortage of water. It is also a fact that many of our villages do not have drinking water. Water management experts say that unless some drastic steps are taken

immediately to expand the irrigation system and to raise the receding ground water level, we will be facing a very severe drinking water shortage by the end of the century.

Has this come to the notice of the Government and, if it has, what additional steps does the Government intend to take to find a solution to the very severe problem of drinking water shortage?

डा० जगन्नाथ मिश्र: सभापति जी, भूतल के पानी के बारे में इस समय इस विभाग की ओर से जो जानकारी प्राप्त की गयी है, उस के अनुसार जो परिस्थितियां बनती जा रही है उन की वजह से आगे के दिनों में कठिनाई होगी और जो व्यवस्था पहले की गयी है, उस में भी बाधाएं आई हैं जल की सतह के नीचे जाने की वजह से। इसलिए वैज्ञानिक रूप से इस का अध्ययन किया जा रहा है, शोध किया जा रहा है कि क्या व्यवस्था की जाए कि जो पहले पानी के स्रोत बनाए गए हैं, वह चालू रहें और जहां पानी की सतह नीचे जाने वाली हैं, वहां पर क्या बेहतर व्यवस्था की जाए।

श्री रामगोपाल यादव: माननीय सभापति जी, यह बहुत ही अफसोस की बात है कि आजादी के इतने अरसे के बाद भी हम गांवों में पीने के लिए शुद्ध जल और पर्याप्त जल की व्यवस्था अभी तक नहीं कर सके हैं। जो व्यवस्था की जा रही है, उस के बारे में गवर्नमेंट को पता है कि नहीं, लेकिन स्थिति यह है कि अभी माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया वाटर-लेवल इतनी तेजी से नीचे जा रहा है कि दो साल पहले जो ट्यूब-वेल लग रहे थे, उनका भी डिस्चार्ज 45 परसेंट, 50 परसेंट रिड्यूस हो गया है।

तो मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में, माननीय मंत्री जी बिहार से हैं, कि इन राज्यों में सारे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कितने दिन लगेंगे? वहां कितने ऐसे गांव हैं जिन में अभी भी पानी की व्यवस्था नहीं है और इस पर कितना धन खर्च होगा? केन्द्र सरकार का हिस्सा कितना होगा और राज्य सरकार का हिस्सा कितना होगा?

डा० जगन्नाथ सिंह: सभापति जी, जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, उस विवरण को अगर माननीय सदस्य देखेंगे तो पाएंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में अच्छी है जहां तक ग्रामीण जल-आपूर्ति का सवाल है। फिर भी जो गांव अभी बचे हुए हैं या जो बस्तियां अभी बची हुई हैं या जहां पानी की समान आपूर्ति नहीं हो रही है, उसे हमने प्राथमिकता दी है व्यवस्था के अंतर्गत और माननीय सदस्य को यह जानकारी होगी कि 1972 से लगातार ग्रामीण जल-आपूर्ति पर बल दिया जा रहा है और विशेषकर तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन बनाकर सारे देश का ध्यान आकर्षित कर दिया था और जब नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने नए सिरे से इस कार्यक्रम को नयी गति दी है और उस मिशन का नाम राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन दिया है और नया संरक्षण किया गया है। उसी संरक्षण के मुताबिक यह चिन्हित किया गया है कि एक लाख चालीस ऐसी बस्तियां है जहां कि जल-आपूर्ति करनी है और जो देश में 13 लाख बस्तियां हैं, उन में से लगभग साढ़े आठ लाख बस्तियों में पानी दिया जा चुका है और बाकी कार्यक्रमों को हम समय-सीमा के भीतर पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते संपूर्ण गांवों को पानी दे दिया जाए और उस के लिए 18 हजार करोड़ रुपए की लागत अनुमानित की जा रही है।

श्री जनार्दन यादव: माननीय मंत्रीजी बिहार की हालत जो अभी बतायी गयी, वह ठीक है? बिहार में छोटा नागपुर और संथाल परगना सहित 18 जिले ऐसे हैं जहां कि अधिकांश गांवों में पीने का पानी नहीं मिलता है।

MR. CHAIRMAN: I have not called you.

श्री जनार्दन यादव: आप बिहार से आते हैं, बिहार की ड्रिंकिंग वाटर की स्थिति ठीक है?

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Chairman, Sir, just now the Minister has stated that various schemes for the supply of safe drinking water have been speeded up. But from the figures of the current three months what we gather is the picture is very pathetic. Sir, in Bihar the target was 11,000 and what they have achieved is only 2 per cent during the current three months. In the month of July and August I do not think that any kind of work can be done. Similarly, regarding Andhra, it is only four per cent of the target. And, for the States which require our help most, like Mizoram,

Nagaland, Sikkim and J & K, it is nil. In the last three months, you have not taken up any such projects in these States which require our help. In view of that, the picture is very tardy. The Government wants to give potable water to all the villages. But, unfortunately, the figures which have been shown for the current year are very pathetic. As such, I would like to know what the schemes of the Minister are to see that these targets which have been mentioned will be achieved by the end of the financial year.

डा० जगन्नाथ मिश्र: सभापति महोदय, यह बात सही है कि पिछले तीन महीने की प्रगति असंतोषजनक है। इस मंत्रालय का भार लेने के तुरन्त बाद जो हमने समीक्षा की तो हमने अनुभव किया कि प्रगति बहुत धीमी है। इसलिए हमने तत्काल सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को प्राथमिकता दी जाए। जिन राज्यों की मैंने अलग-अलग समीक्षा की है, खास तौर से बिहार और आन्ध्र प्रदेश इन दोनों प्रदेशों में मैं स्वयं गया था और इन दोनों प्रदेशों में वहां की स्थिति मैंने देखी है। तो वहां भी हमने ध्यान आकृष्ट किया है कि बिहार में जो राशि आवंटित की गई है उसका व्यय नहीं हुआ है। यही स्थिति आन्ध्र प्रदेश की भी है। हमने सभी मुख्य मंत्रियों से कहा है कि भारत सरकार द्वारा जो राशि दी जा रही है उसका प्रयोग प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

Enactment of Lok Pal Bill

*62. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:[†]
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the response of the leaders of all the political parties to the letter addressed by the Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions on 31st May, 1995 asking for comments to bring about consensus on the enactment of Lokpal Bill in the current Session; and

(b) the names of leaders or MPs who have responded to the invitation to send suggestion on Lokpal including the response of major National parties and by when Government are planning to call a meeting of all political parties and groups to find out a consensus?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) 49 Hon'ble Members of Parliament were addressed out of which 5 Members have responded till 28.7.95.

(b) Shri E. Ahamed, Muslim League, Shri Jaswant Singh, BJP, Shri Chimanbhai Mehta, Independent, Ms. Dil Kumari Bhandari, SSP, Shri Chaturanan Mishra, CPI have responded to the invitation of MOS(PP). Shri Jaswant Singh has suggested that the matter be left to the next Lok Sabha.

श्री चिमनभाई मेहता: सर, यह बहुत निराशाजनक बात है कि मेरे पूछे गए प्रश्न में मैंने पूछा है कि लोकपाल के बारे में सर्वसम्मति तैयार करने हेतु सरकार सभी राजनैतिक दलों और गुटों की एक बैठक कब तक बुलाने पर विचार कर रही है। अब प्रश्न तो मैंने यह पूछा है कि आप बैठक कब बुलायेंगे आप देख लीजिए सभापति महोदय कि जो जवाब दिया गया है, यह जो मुख्य प्रश्न है उनका उत्तर उसके हिसाब से कोई जगह नहीं पा रहा है। आलतू-फालतू की बातें ही बताई गई हैं कि कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोकपाल के बारे में कब मीटिंग बुलाने जा रही हैं यह नहीं बताया है। बार-बार आपने टाला है और पांच वर्ष से टाल रहे हैं, अब कितने दिन और टालेंगे? यह तो अनयूजुअल बातें हो रही हैं। नॉन-आफीशियल रेज़ोल्यूशन जब होता है तब भी गवर्नमेंट टालने की कोशिश कर रही है।

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Therefore, my question is, when are you going to call a meeting to bring about a consensus on the Lokpal Bill? That is my main point.

SMT. MARGARET ALVA: Sir, I am sorry, but I would like to draw the attention of the hon. Member to this. He says that my answer is irrelevant. The first part of the question is about the

[†]The Question was actually asked on the floor of the House by Chimanbhai Mehta.